Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General of India on State Public Sector Enterprises for the period ended March 2023, Government of Uttar Pradesh, Report No. 9 of the year 2025 (Performance and Compliance Audit-Commercial) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 20.02.2026

Name of the Newspaper	हिंदुस्तान
Date	**21.02.2026**
Edition	हिंदी
Page No.	**12**

27 उद्यमों को 32 हजार करोड़ का घाटा

लखनऊ। सीएजी की वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के 27 उद्यमों (एसपीएसई) 32,393 .08 करोड़ रुपये का घाटा सामने आया है जबकि 39 एसपीएसई को 2,169 .50 करोड़ का लाभ हुआ था। सीएजी ने 68 एसपीएसई के लाभ व हानि तथा कार्यों का विश्लेषण किया, जिनमें दो एसपीएसई को कोई लाभ-हानि नहीं हुई। रिपोर्ट के अनुसार 68 क्रियाशील एसपीएसई (प्रथम वित्तीय विवरण प्रस्तुत न करने वाले चार एसपीएसई को छोड़कर) का टर्नओवर 92,696 .60 करोड़ था, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (22,57,575 करोड़) का 4 .10 प्रतिशत था।

Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General of India on State Public Sector Enterprises for the period ended March 2023, Government of Uttar Pradesh, Report No. 9 of the year 2025 (Performance and Compliance Audit-Commercial) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 20.02.2026

Name of the Newspaper	**अमर उजाला**
Date	**21.02.2026**
Edition	**हिंदी**
Page No.	**-**

सार्वजनिक क्षेत्र के सात निगमों ने तीन साल में पहुंचाई 32 हजार करोड़ की चोट

सीएजी रिपोर्ट : कुल नुकसान में इन निगमों की 99% हिस्सेदारी, घाटे वाले निगमों में ऊर्जा सेक्टर आगे

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। सार्वजनिक क्षेत्र के 27 उद्यम राज्य सरकार के लिए बोझ बन गए हैं। इन उपक्रमों का वित्त वर्ष 21-22 और 22-23 (एक को छोड़कर) में नुकसान 32393 करोड़ रुपये से ज्यादा था। इनमें से सात निगमों ने 32202 करोड़ रुपये से ज्यादा की चोट पहुंचाई। यानी कुल नुकसान में इन सात निगमों का योगदान 99 फीसदी से ज्यादा है। कुल नुकसान में 45 फीसदी योगदान उप्र पॉवर कॉर्पोरेशन का है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की मार्च 2023 तक जारी रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है।

शुक्रवार को विधान मंडल के दोनों सदनों के पटल पर राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर सीएजी रिपोर्ट रखी गई। इसके मुताबिक, कुल 113 निगमों में से 86 सरकारी कंपनी, 21 सरकार से नियंत्रित और 6 सांविधिक निगम हैं। इनमें से 72 क्रियाशील और 41 निष्क्रिय हैं। 13 की तालाबंदी हो चुकी है।

72 क्रियाशील निगमों में से लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट और उप्र राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम ने रिपोर्ट ही नहीं दी। 68 क्रियाशील निगम (चार को छोडकर, जिन्होंने अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किए थे) का टर्नओवर (52696.60 करोड) था। वर्ष 2022-23 के लिए प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का यह 4.10 प्रतिशत था।

राजकीय निर्माण निगम ने बिना सूचना जारी कर दिए 1047 करोड़ के वर्कऑर्डर...राजकीय निर्माण निगम ने 641.45 करोड़ के अर्जित ब्याज को कोषागार में जमा नहीं किया। साथ ही संविदाकारों से एडवांस पर ब्याज के रूप में वसूली गए 7.47 करोड़ को भी सरकारी खाते में जमा करने के बजाय अपनी आय का हिस्सा बता दिया। निर्माण निगम के इकाई प्रभारियों ने भी जमकर अनियमितता बरती। एमडी के आदेश के बिना और बोर्ड को सूचना दिए बगैर 1047 करोड़ के 52 कार्य आदेश (वर्क ऑर्डर) जारी कर दिए। ये सभी आदेश टेंडर के बजाय सूचीबद्ध ठेकेदारों से कोटेशन लेकर बांट दिए गए। निगम को 137 कार्यों में वित्तीय गड़बड़ियों से 165.72 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा।

100 करोड़ से ज्यादा फायदे वाले निगम

निगम	फायदा (करोड़ रुपये में)
पश्चिमांचल विद्युत निगम	991
उप्र जल विद्युत निगम	275
उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम	235
उप्र राज्य भंडारण निगम	165
उप्र आवास एवं विकास परिषद	144
उप्र राजकीय निर्माण निगम	120

100 करोड़ से ज्यादा नुकसान वाले निगम

उप्र पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन	556
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम	6610
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम	4819
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम	5073
उप्र पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	14572
उप्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	319
उप्र जल निगम	250

ऊर्जा के बाद नोएडा एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा इक्विटी निवेश

- सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने वर्ष 21-22 और 22-23 में ऊर्जा के बाद सबसे ज्यादा इक्विटी निवेश नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया। इन दो वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 निगमों में 24795 करोड़ का निवेश किया गया। इसमें करीब 21500 करोड़ रुपये उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम, पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन और उप्र पॉवर कॉर्पोरेशन में किया गया।
- दूसरे नंबर पर 1325 करोड़ के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तीसरे नंबर पर 1257 करोड़ के साथ यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन रहा। इसके अलावा नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, राज्य सड़क परिवहन निगम, मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन, बरेली स्मार्ट सिटी, कानपुर स्मार्ट सिटी, मुरादाबाद स्मार्ट सिटी और प्रयागराज स्मार्ट सिटी भी शामिल हैं।

Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General of India on State Public Sector Enterprises for the period ended March 2023, Government of Uttar Pradesh, Report No. 9 of the year 2025 (Performance and Compliance Audit-Commercial) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 20.02.2026

Name of the Newspaper	**दैनिक जागरण**
Date	**21.02.2026**
Edition	**हिंदी**
Page No.	**12**

तकनीकी स्वीकृति के बिना कराए 2,058 करोड़ के कार्य

27 एसपीएसई को 32,393.08 करोड़ की हानि, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में तथ्य उजागर

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) ने तकनीकी स्वीकृति के बिना ही 2,058.35 करोड़ रुपये के काम करवा डाले हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में यह राजफाश किया गया है। वर्ष 2022-23 की इस रिपोर्ट को शुक्रवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया गया। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 113 में से 27 एसपीएसई 32,393.08 करोड़ रुपये के घाटे में थे, जबकि 39 ने 2,169.50 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया।

रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी स्वीकृति के बिना कराए जाने वाले 2,058.35 करोड़ रुपये के कार्यों में करीब 200.09 करोड़ रुपये से प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय प्रयागराज, करीब 341.57 करोड़ रुपये से विधान भवन का विस्तार, 236.26 करोड़ रुपये से राजकीय मेडिकल कालेज अंबेडकर नगर, 216.77 करोड़ रुपये से सोबन सिंह जीना राजकीय मेडिकल कालेज, अल्मोड़ा, 160.11 करोड़ रुपये से जिला कारागार प्रयागराज, 183.91 करोड़ रुपये से नवीन जिला कारागार, इटावा व 189.16 करोड़ रुपये से महाराजा सुहेलदेव राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच सहित 34 निर्माण कार्य शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2023 में 86 सरकारी कंपनियां, सरकार द्वारा नियंत्रित 21 अन्य कंपनियां व छह सांविधिक निगम थे। 72 एसपीएसई संचालित जबकि 41 निष्क्रिय थे। घाटे में चल रहे शीर्ष पांच एसपीएसई में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को 14,572.24 करोड़ रुपये, पूर्वांचल डिस्काम को 6,610.27 करोड़ रुपये, दक्षिणांचल डिस्काम को 5,073.77 करोड़, मध्यांचल डिस्काम को 4,819.92 करोड़ व पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को 556.26 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। पश्चिमांचल डिस्काम ने 991.67 करोड़ रुपये, जल विद्युत वितरण निगम ने 275.88 करोड़ रुपये, राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने 235.66 करोड़, उप्र राज्य भंडारण निगम ने 165.53 करोड़ व आवास एवं विकास परिषद ने 144.68 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है।

इन कंपनियों ने नहीं की महिला निदेशकों की नियुक्तिः कंपनी अधिनियम के तहत केंपनियों के निदेशक मंडल में न्यूनतम एक महिला निदेशक की नियुक्ति होनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार 15 कंपनियों (जल विद्युत निगम, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, चीनी एवं गन्ना विकास निगम, मुरादाबाद स्मार्ट सिटी, लखनऊ स्मार्ट सिटी, स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, सेतु निगम, स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, यूपी डेस्को) ने एक भी महिला निदेशक नहीं बनाया। पावर ट्रांसमिशन, पावर कारपोरेशन, दक्षिणांचल डिस्काम, दी प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यूपी (पिकप) व प्रयागराज स्मार्ट सिटी ने महिला निदेशक की नियुक्ति तय समय के लिए नहीं की।

निर्माण निगम ने नहीं लागू की सीएसआर नीतिः रिपोर्ट के अनुसार राजकीय निर्माण निगम और यूपी मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति ही लागू नहीं की। यूपी डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन, यूपी मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन, निर्माण निगम, सेतु निगम, यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम ने सीएसआर फंड होने पर भी खर्च नहीं किया।

- यूपी पावर कारपोरेशन को 14,572.24 करोड़ का घाटा
- 39 एसपीएसई ने अर्जित किया 2,169.50 करोड़ रुपये का लाभ

15 कंपनियों ने एक भी महिला निदेशक नहीं बनाया

सीएजी की रिपोर्ट के अन्य प्रमुख बिंदु

- 35 एसपीएसई ने निदेशक बोर्ड की बैठकें ही आयोजित नहीं की।
- सरकारी निधियों पर अर्जित 641.45 करोड़ रुपये के ब्याज को राजकोष में जमा नहीं किया गया।
- 1047.67 करोड़ रुपये के औजार, मशीनरी, संयंत्र की खरीद व श्रमिकों की नियुक्ति नियमों के विपरीत की गई।
- सैनिक स्कूल अमेठी, राजकीय एलोपैथिक कालेज बहराइच, मेडिकल कालेज अल्मोड़ा, राम मनोहर लोहिया आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ सहित कई कार्यालयों के लिए 1.54 करोड़ रुपये के फर्नीचर व अन्य सामग्री जेम पोर्टल के माध्यम से नहीं खरीदी गई।
- ग्रेटर नोएडा में स्मार्ट सिटी के सूचना संचार पर खर्च को लेकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ठेका दिया गया। दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर ठेका निरस्त हो गया लेकिन दो करोड़ की धरोहर राशि नहीं जब्त की गई।
- राज्य सड़क परिवहन निगम ने निविदा सूचना प्रकाशित किए बिना कम दरों पर अनुबंध किया, जिससे 2.15 करोड़ का घाटा हुआ।

Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General of India on State Public Sector Enterprises for the period ended March 2023, Government of Uttar Pradesh, Report No. 9 of the year 2025 (Performance and Compliance Audit-Commercial) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 20.02.2026

Name of the Newspaper	**अमर उजाला**
Date	**22.02.2026**
Edition	**हिंदी**
Page No.	**03**

दो साल में पांच निगमों की कुल संपत्ति 10 हजार करोड़ रुपये घटी

सीएजी रिपोर्ट : राज्य के सार्वजनिक उपक्रम वित्तीय संकट में, देनदारियां पूंजी से ज्यादा

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को सबसे ज्यादा 6061 करोड़ रुपये का नुकसान

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (एसपीएसई) की वित्तीय स्थिति गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। पिछले दो वर्षों में पांच प्रमुख निगमों की कुल संपत्ति (नेटवर्थ) में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत सीएजी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

सबसे अधिक नुकसान दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को हुआ, जिसकी नेटवर्थ में 6061.51 करोड़ रुपये की कमी आई। इसके बाद उत्तर प्रदेश जल निगम (1820.15 करोड़ रुपये) और केस्को कानपुर (1755.65 करोड़ रुपये) की नेटवर्थ में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। वहीं यूपीएफसी की नेटवर्थ 719.11 करोड़ रुपये और पिकप की 241.17 करोड़ रुपये घटी।

16 उपक्रमों की पूंजी पूरी तरह समाप्त

68 एसपीएसई के विश्लेषण में पता चला कि 16 सरकारी उपक्रमों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इन कंपनियों की कुल पूंजी (समादत्त पूंजी और जमा लाभ) 26,891.32 करोड़ रुपये थी। लेकिन इन पर कुल नुकसान और बाकी खर्च 37,979.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यानि इन कंपनियों का घाटा उनकी कुल पूंजी से भी ज्यादा हो चुका है। साफ है कि इनकी देनदारियां बहुत बढ़ गई हैं और उनकी पूरी पूंजी खत्म (शून्य) हो चुकी है।

सरकार का भारी निवेश, बढ़ती निर्भरता

31 मार्च 2023 तक 72 क्रियाशील एसपीएसई में कुल निवेश 412768.89 करोड़ रुपये रहा। इसमें 282529.29 करोड़ रुपये इक्विटी और 130238.60 करोड़ रुपये दीर्घावधि ऋण शामिल है। कुल निवेश में से 174333.04 करोड़ रुपये (लगभग 42 प्रतिशत) राज्य सरकार का योगदान है। बजटीय सहायता के रूप में अनुदान और सब्सिडी 2021-22 के 23439.82 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 28,318.68 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष के अंत तक बकाया प्रत्याभूति प्रतिबद्धताएं भी 37387.30 करोड़ रुपये से बढ़कर 46,641.91 करोड़ रुपये तक पहुंच गईं।

लेखा प्रस्तुत करने में देरी

सीएजी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 113 सार्वजनिक उपक्रमों में से केवल 10 ने 2022-23 के वित्तीय विवरण 30 सितंबर 2023 तक प्रस्तुत किए। वहीं, 62 क्रियाशील एसपीएसई के 324 वार्षिक लेखे लंबित रहे। 28 निष्क्रिय एसपीएसई के 603 वार्षिक लेखे बकाया हैं। 11 समापनाधीन एसपीएसई के 120 वार्षिक लेखे एक से 41 वर्ष तक लंबित पाए गए।

स्वतंत्र और महिला निदेशकों की कमी

32 एसपीएसई में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक अनिवार्य थे, लेकिन 26 में एक भी स्वतंत्र निदेशक नहीं था। दो एसपीएसई में केवल एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त था। जिन छह एसपीएसई में स्वतंत्र निदेशक थे, उनकी बोर्ड बैठकों में उपस्थिति 50 से 80 प्रतिशत के बीच रही। इसी तरह 31 एसपीएसई में कम से कम एक महिला निदेशक अनिवार्य थी, लेकिन 10 उपक्रमों में पूरे वर्ष एक भी महिला निदेशक नहीं रहीं। 16 में वर्षभर महिला निदेशक मौजूद रहीं, जबकि पांच में आंशिक अवधि के लिए ही नियुक्ति रही।

एसपीएसई की सेहत पर गंभीर सवाल

वित्तीय घाटे, बढ़ती देनदारियों, लेखा प्रस्तुत करने में देरी और बोर्ड संरचना में कमियों के बीच राज्य के एसपीएसई की सेहत पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते ठोस वित्तीय और प्रशासनिक सुधार न किए गए तो भविष्य में स्थिति और जटिल हो सकती है।

Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General of India on State Public Sector Enterprises for the period ended March 2023, Government of Uttar Pradesh, Report No. 9 of the year 2025 (Performance and Compliance Audit-Commercial) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 20.02.2026

Name of the Newspaper	**Hindustan Times**
Date	**21.02.2026**
Edition	**English**
Page No.	**08**

CAG report: 'UPPCL contributed 45% of total losses of SPSEs'

Umesh Raghuvanshi
uraghuvanshi@hindustantimes.com

LUCKNOW: Uttar Pradesh government's 39 out of 72 functional state public sector enterprises (SPSEs) earned a profit of only Rs 2169.50 crore while its 27 SPSEs incurred losses amounting to Rs 32,393.08 crore.

Four SPSEs did not submit their first financial accounts while two reported no profit no loss, as per their latest finalised financial statements, according to the Comptroller and Auditor General of India (CAG) report on SPSEs (for the period ending on March 31, 2023) tabled in the state legislative assembly on Friday. The UP Power Corporation Limited (UPPCL) contributed nearly 45% (Rs 14572.24 crore) of the total loss of the SPSEs, it stated.

The CAG report pointed out that seven of the 27 SPSEs incurred a loss of Rs 100 crore or more and contributed to 99% of the total loss. These included five SPSE's of the power sector. Besides UPPCL, which incurred a loss of Rs 14572.24 crore (2022-2023), other power sector companies that figured on the list included Purvanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited that incurred a loss of Rs 6610.27 crore (2022-2023). The Dakshinanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited incurred a loss of Rs 5073.77 crore (2022-2023) while Madhyanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited's total loss was Rs 4819.92 crore in 2022-2023.

UP Power Transmission Corporation incurred a loss of Rs 535.26 crore, according to the financial statement of 2021-2022. The CAG observed that the 39 SPSEs that earned profits included six that contributed more than 89% (Rs 1933.80 crore) of the total profit of Rs 2169.50 crore. The PVVNL alone accounted for 46% (Rs 991.67

FOUR SPSES DID NOT SUBMIT THEIR FIRST FINANCIAL ACCOUNTS WHILE TWO REPORTED NO PROFIT NO LOSS, AS PER THEIR LATEST FINALISED FINANCIAL STATEMENTS

Others that contributed to the profit included UP Jal Vidyut Nigam Limited (12.72%), UP Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (10.86%), UP State Warehousing Corporation (7.63%), UP Awas Vikas Parishad (6.67%) and UP Rajya Nirman Nigam Limited (5.55%).

It may be mentioned that 65 out of 72 functional SPSEs, including 12 SPSEs of the power sector, had 4.10% share of turnover in the gross state domestic product (GSDP) in 2022-2023. This included turnover of Rs 77,063.32 crore (3.41 percent share of turnover) from the power sector while other than power sector companies contributed only 0.69 percent.

The CAG analysis revealed that the net worth of 16 SPSEs had completely eroded. The paid-up capital, free reserves and surplus of these SPSEs was Rs 26,891.32 crore while accumulated losses and deferred revenue expenditure stood at Rs 37,929.25 crore. Of these 16 SPSEs, the maximum net worth erosion was observed in five SPSEs that included DVVNL (Rs -6061.51 crore), UP Jal Nigam (Rs 1820.15 crore), Kanpur Electricity Supply Company Limited (Rs 1755.65 crore), UP Financial Corporation Limited (Rs 719.11 crore) and The Pradeshiya Industrial and Investment Corporation of UP Limited (Rs 241.17